सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

प्रेरणा

रिश्तों का गलत इस्तेमाल
कभी मत करना,
अच्छे लोग जिंदगी में
बार बार नहीं आते...

साप्ताहिक मौसम

दिन	अधिकतम	न्यूनतम
शुक्रवार	33°	25°
शनिवार	33°	26°
रविवार	33°	27°
सोमवार	33°	26°
मंगलवार	36°	26°
बुधवार	32°	24°
वीरवार	32°	25°

*आंकड़े आईएमडी के अनुसार

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-7 • 08 AUGUST TO 14 AUGUST 2025 • VOLUME 03 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184
INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE
CONSULTING DESIGN TRAINING
ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

CONFUSED ABOUT CAREER!
Unsure of what to do after 10th/12th/Graduation?
Whether to Study in India or Abroad?

What should I do after 10th-Science, Commerce or Arts?
Should I consider Computer or Mechanical Engineering?
What is better for me - MBA in Marketing or MBA in Finance?
Should I pursue Chartered Accountancy or Law after 12th?
Do I have the aptitude for Architecture and Designing?
Get Career Guidance from our Expert Career Counseling Team Free of Cost

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact :9317776662, 9317776663
REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.
*T&C apply

लैंड पूलिंग पॉलिसी पर हाई कोर्ट ने चार हफ्तों के लिए लगाई रोक

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति पर चार हफ्तों के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने एक दिन की अंतरिम रोक लगाई थी और पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। भगवंत मान सरकार द्वारा स्वीकृत पंजाब लैंड पूलिंग नीति 2025 का मकसद राज्य में नियोजित और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देना है, खासकर अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाकर। इसका एक प्रमुख पहलू इसकी स्वैच्छिक प्रकृति है जो अनिवार्य अधिग्रहण विधियों के विपरीत किसानों को विकास के लिए अपनी भूमि को पूल करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

जस्टिस अनुपिंदर ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा ने पंजाब के महाधिवक्ता (एजी) से अदालत को यह बताने को कहा कि क्या नीति में भूमिहीन मजदूरों और अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान है, जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो अपनी आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि उन्हें अदालत को यह भी बताना होगा कि नीति अधिसूचित करने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एवं अन्य बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ (2023) में निर्देश दिया है कि शहरी विकास की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किया जाना चाहिए। लैंड पूलिंग योजना में किसान अपनी जमीन को पूल करके शहर के नियोजित विकास में योगदान देते हैं। देश में यह योजना सबसे पहले 1915 के बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत शुरू की गई थी जिसमें जमीन के कई छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर उनका विकास किया जाता था। इसके बाद किसानों को अपनी जमीन का एक हिस्सा वापस मिल जाता है जिसकी कीमत पहले से ज़्यादा होती है। यह व्यवस्था जबरन जमीन अधिग्रहण को रोकती है और सभी को उचित मुआवजा देकर साझा विकास को बढ़ावा देती है। पंजाब सरकार भी जमीन के विकास के लिए यह योजना लेकर आई है।

बाजवा ने इसे पंजाब के लोगों की जीत बताया

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को आप सरकार की विवादास्पद लैंड पूलिंग नीति पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थगन का स्वागत किया और इसे 'पंजाब के लोगों की ऐतिहासिक जीत' बताया। उन्होंने कहा कि इस बेहद दोषपूर्ण और असंवैधानिक नीति पर रोक लगाने के लिए माननीय हाईकोर्ट का आभारी हूँ। मैंने बार-बार चेतावनी दी थी कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की मूल भावना का उल्लंघन करता है, जो डॉ. मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रगतिशील कानून है। 2013 का अधिनियम भूस्वामियों के लिए मज़बूत क़ानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं: 70-80% भूस्वामियों की सहमति, उचित मुआवज़ा, सामाजिक प्रभाव आकलन और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन। बाजवा ने कहा कि यह ज़मीन का पूलिंग नहीं था—यह साफ़-साफ़ ज़मीन का धोखा था। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब के हित में नहीं, बल्कि दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट लॉबी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने का आरोप लगाया।

...तो किसान बर्बादी की ओर धकेल दिए जाते : बलबीर सिद्धू

एसएएस नगर (जालंधर ब्रीज). कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने हाई कोर्ट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल पंजाब के किसानों, पंजाब की ज़मीनों की रक्षा करता है, बल्कि पंजाबियत और कृषि-आधारित आर्थिक मॉडल की भी रक्षा करता है। बलबीर सिद्धू ने कहा कि अगर 'आप' सरकार की लैंड पूलिंग नीति लागू हो जाती, तो पंजाब को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों की ज़मीन हड़पने की एक चाल थी, जिसके खिलाफ किसानों और हमारी कांग्रेस पार्टी ने ज़ोरदार आवाज़ उठाई। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट का यह फैसला सत्य की जीत है और यह साबित करता है कि लोकतंत्र में आम आदमी की आवाज़ आज भी सुनी जाती है। उन्होंने इस मुद्दे को हाईकोर्ट तक पहुँचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी वकीलों, किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया।

ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी बोले- मुझे व्यक्तिगत रूप से कीमत चुकानी पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार

नई दिल्ली. भारत और अमेरिका के रिश्तों में ट्रंप के टैरिफ के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। हाल ही में लगातार ट्रंप ने जो पाकिस्तान भारत के बीच सीजफायर कराने का क्रेडिट लिया था उस पर जब पीएम मोदी ने संसद में अपनी प्रतिक्रिया दी जिससे भी ट्रंप काफी ज्यादा तिलमिला गये। बस इसके बाद ही उन्होंने भारत पर 25 प्रतिशत का ट्रंप टैरिफ लगा दिया। अब भारत-अमेरिका के बीच जो स्थिति है इस पर पीएम मोदी में भारत का रुख साफ करते हुए अमेरिका के लिए एक और स्टेटमेंट जारी कर दिया है। ये स्टेंटमेंट किसी और ने नहीं बल्कि पीएम मोदी ने दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को

कहा कि किसानों के हितों की रक्षा उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और देश उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगा। उनकी यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने के एक दिन बाद आई है। दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें पता है कि उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। मेरा मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं इसके लिए तैयार हूँ। बुधवार को ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया। इसके साथ ही कुछ अपवादों को छोड़कर अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है।

कपिल शर्मा के कैफे पर फिर से फायरिंग, गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने ली जिम्मेदारी

टोरांटो. मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरी स्थित कैफे पर फिर से फायरिंग हुई है। गोल्डी ढिल्लों नामक गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी

ली। फायरिंग में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक कार में बैठे कुछ लोग कैफे की ओर गोलीबारी करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो 9 सेकंड का है जिसमें 12 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। स्थानीय पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक इस गैंग ने कहा कि जय श्री राम, सत श्री अकाल, राम राम सभी भाइयों को। आज जो कपिल शर्मा के कैप्स कैफे सरी में फायरिंग हुई है, उसकी जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है। हमने उसको फोन किया लेकिन इसे रिंग सुनाई नहीं दी, जिस वजह से हमें करवाई करनी पड़ी। फिर फोन करने पर रिंग सुनेगा तो अगली कार्रवाई जल्दी ही मुंबई में करेंगे।

सीएम और संत निरंजन दास ने डेरा सचखंड बल्लां में एसटीपी का किया शिलान्यास

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वीरवार को डेरा सचखंड बल्लां में लगभग 3.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और मुख्य पंपिंग स्टेशन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डेरा सचखंड बल्लां में नतमस्तक होकर डेरा प्रमुख संत निरंजन दास जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रद्धा प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महान धार्मिक नेताओं के चरण स्पर्श और इस पावन स्थल के दर्शन का अवसर पाकर वे स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह धरती सदैव विश्व शांति, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्यों को प्रोत्साहित करती रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए मार्ग पर चलते हुए पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा को भी प्राथमिकता दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण पहल कर चुकी है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के एक नए युग की शुरुआत की है और आज शैक्षणिक परिणामों में पंजाब देश का नेतृत्व कर रहा है।

तरन तारन से आईईडी बरामद

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पाकिस्तान के आईएसआई समर्थित सरहद पार के आतंकवादी नैट्टवर्कों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी हरविन्दर रिन्दा और आतंकवादी लखबीर लंडा द्वारा रची गई बड़ी आतंकवादी साजिश को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने कहा कि एजीटीएफ की टीमों को पाकिस्तान से भेजी गई इंप्रोवाईज़ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) की खेप के बारे भरोसेयोग सूत्रों से ख़ुफ़िया सूचना मिली थी। एजीटीऐफ ने तरनतारन पुलिस के साथ तालमेल करके ज़िले में तलाशी मुहिम चलाई और तरनतारन के नौशहरा पन्नूआं क्षेत्र से एक आईईडी बरामद की। डीजीपी ने कहा कि आईईडी को तुरंत सुरक्षित ढंग से एक निर्धारित स्थान पर ले जाया गया, जहाँ इसको विस्फोटक आर्डीनैंस डिस्पोज़ल टीम द्वारा कंट्रोल्ड डैटोनेशन के अंतर्गत सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया।

पंजाब पुलिस ने आपराधिक पृष्टभूमि वाले व्यक्तियों के घरों पर एक ही समय की छापेमारी

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच अनुसार आगामी स्वतंत्रता दिवस के शांतिपूर्ण जश्नों को यकीनी बनाने के लिए पंजाब पुलिस ने आज समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करते हुये पिछले तीन सालों में हथियार एक्ट के अधीन तीन से अधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों के घरों पर एक ही समय छापेमारी की। यह छापेमारी डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र चल रहे विशेष ऑपरेशनों के हिस्से के तौर पर की गई है। स्पैशल डीजीपी कानून और व्यवस्था अर्पित शुक्ला ने बताया कि यह आपरेशन राज्य भर में एक ही समय चलाया गया और सभी सीपीज़/ ऐसऐसपीज़ को गज़टिड रैंक के अधिकारी की निगरानी में अपेक्षित संख्या में पुलिस टीमें तैनात करने के लिए कहा गया जिससे इन व्यक्तियों के घरों की जांच की जा सके। उन्होंने बताया कि 120 पुलिस पार्टियाँ, जिनमें 1000 से अधिक पुलिस कर्मचारी शामिल थे, ने पिछले तीन सालों में हथियार एक्ट के अंतर्गत तीन से अधिक मामलों में शामिल कम से कम 205 व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की।

चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने जताया संदेह, बोले- फर्जी तरीके से हो रही है वोटिंग

नई दिल्ली. कांग्रेस बिहार में एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। इसी कड़ी में वीरवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है कि सत्ता-विरोधी भावना हर लोकतंत्र में हर पार्टी को प्रभावित करती है। लेकिन किसी न किसी वजह से, लोकतांत्रिक ढाँचे में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मूल रूप से इस सत्ता-विरोधी भावना से ग्रस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल कुछ कहते हैं, जैसा आपने हरियाणा चुनाव में देखा, मध्य प्रदेश चुनाव में देखा, और फिर अचानक नतीजे पूरी तरह से अलग दिशा में चले जाते हैं, और भारी उलटफेर होते हैं। राहुल ने कहा कि इसमें हमारा अपना आंतरिक सर्वेक्षण भी शामिल है, जो काफ़ी परिष्कृत है। तो सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, जनमत सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, नियमित सर्वेक्षण हमें कुछ दिखा रहे थे, और अचानक हमें पता चल रहा है कि नतीजे उलटे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान की नींव इस तथ्य पर टिकी है कि एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है। इसलिए, जब हम चुनाव की योजना बना रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी बात यह होती है कि एक व्यक्ति, एक वोट का विचार कितना सुरक्षित है।

किसान-केंद्रित पहलों के कारण भारत में कृषि क्रांति तेज गति से जारी

जालंधर ब्रीज. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में निरंतर सुधारों और किसान-केंद्रित पहलों के कारण कृषि क्षेत्र में निरंतर प्रगति हुई है और देश ने धान, गेहूं, मक्का, मूंगफली और सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। कृषि वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसल उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024-25 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 353.96 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन होगा और वर्ष 2014-15 (252.02 मिलियन टन) की तुलना में यह 40 प्रतिशत अधिक रहेगा।

1960 के दशक से पहले की जड़ता और खाद्य असुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए आज भारतीय कृषि खाद्य अधिशेष प्राप्त करने की स्थिति में आ गयी है, जिससे माल्थस की यह धारणा गलत साबित होती है कि जनसंख्या वृद्धि, खाद्य उत्पादन की तुलना में अधिक हो जाएगी। 1967 में, विलियम और पॉल पैडॉक ने भारत में अकाल की भविष्यवाणी की थी। उनका दावा था कि देश अपनी बढ़ती आबादी का पेट नहीं भर पाएगा। उन्होंने खाद्य सहायता के खिलाफ विवादास्पद तर्क दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भविष्य में भुखमरी और बढ़ेगी। उच्च उपज वाले चावल और गेहूं की किस्मों, कृषि रसायनों और सिंचाई से संचालित हरित क्रांति ने पैडॉक की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। भारत का खाद्यान्न उत्पादन 1966-67 के 74 मिलियन टन से बढ़ाकर 1979-80 तक 130 मिलियन टन हो गया। वार्षिक वृद्धि 8.1 मिलियन टन (2014-2025) के शिखर-बिंदु को छूते हुए 354 मिलियन टन तक पहुंच गई। बागवानी फसलें भी 1960 के दशक के 40 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में 334 मिलियन टन हो गई, जिसमें हाल ही में 7.5 मिलियन टन की वार्षिक वृद्धि हुई है। विपरीत परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम किस्मों और अनुकूल कृषि पद्धतियों में प्रगति के कारण फसल उत्पादन में भी अधिक स्थिरता आयी है।

शिवराज सिंह चौहान
(केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार)

भारत के डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1970 के दशक में शुरू हुई श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन को 20 मिलियन टन से बढ़ाकर 2023-24 तक 239 मिलियन टन कर दिया, जो पूरे यूरोप के बराबर है। 1980 के दशक की नीली क्रांति ने मछली उत्पादन को 2.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 2024-25 तक 19.5 मिलियन टन कर दिया, जिससे भारत दूसरा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य उत्पादक और निर्यातक बन गया। मुर्गीपालन, घरेलू गतिविधि से आगे बढ़कर एक उद्योग के रूप में विकसित हुआ, जिसमें अंडों का उत्पादन 10 बिलियन से बढ़कर 143 बिलियन हो गया और इसी अवधि में मुर्गी के मांस का उत्पादन 113 हजार टन से बढ़कर 5,019 हजार टन हो गया। 2014-15 और 2023-24 के बीच, पशु-स्रोत से प्राप्त खाद्य के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई: दूध में सालाना 10.2 मिलियन टन, अंडों में 6.8 बिलियन इकाई, ब्रॉयलर मांस में 217 हजार टन और मछली (मुख्य रूप से जलीय कृषि) में 0.78 मिलियन टन की वृद्धि हुई। प्रजनन, संसाधन प्रबंधन और कुशल जनशक्ति में तकनीकी प्रगति ने इस तेज वृद्धि को गति दी है। फल, सब्ज़ियां और पशु उत्पाद जैसे उच्च-मूल्य वाले खाद्य पदार्थ अब खाद्यान्न वृद्धि से आगे निकल रहे हैं, जो कृषि विविधीकरण, बेहतर पोषण, किसानों की आय और जलवायु विषम परिस्थितियों के प्रति सहनीयता में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

भारत की खाद्य उत्पादन सफलता पोषण, किसानों की आय, जलवायु की विषम परिस्थितियों के प्रति सहनीयता और निर्यात को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी व नीति की परिवर्तनकारी भूमिका को दर्शाती है। आईसीएआर के शोध से पता चलता है कि कृषि में निवेश पर उच्च आय प्राप्त होती है- अनुसंधान और विस्तार पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये पर क्रमशः 13.85 रुपये और 7.40 रुपये। पीएमकेएसवाई (सिंचाई), पीएम-किसान (प्रत्यक्ष किसान सहायता), राष्ट्रीय पशुधन मिशन और नीली क्रांति जैसी हाल की सरकारी पहलों ने संसाधनों के उपयोग को बढ़ाकर, जोखिमों को कम करके और कृषि-खाद्य प्रणाली में प्रौद्योगिकी अपनाने को प्रोत्साहन देकर कृषि विकास को और मजबूती दी है। भारत में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में पिछले कुछ दशकों के दौरान खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धिशील प्रगति देखी गई है।

2047 तक, भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसलिए इसकी अर्थव्यवस्था को सालाना 7.8 प्रतिशत की दर से वृद्धि करनी होगी। अनुमान है कि 2047 तक देश की जनसंख्या 1.6 अरब हो जायेगी- जिसमें से आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी। इस बदलाव से खाद्यान्न की कुल मांग दोगुनी हो जाएगी, फलों, सब्जियों और पशु-आधारित खाद्य पदार्थों की मांग तिगुनी होने की उम्मीद है, जबकि अनाज की मांग स्थिर रहेगी, जिससे अधिशेष की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, बढ़ते शहरीकरण और औद्योगीकरण के कारण कृषि भूमि 180 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 176 मिलियन हेक्टेयर और औसत भूमि जोत 1 से घटकर 0.6 हेक्टेयर रह जाएगी। इससे जल और कृषि रसायनों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे संसाधनों का क्षरण होने का खतरा होगा। जलवायु परिवर्तन और भी बड़ा जोखिम है, जो स्थायी कृषि और ग्रामीण आजीविका को खतरे में डालता है।

भारत की उभरती कृषि-खाद्य चुनौतियां, उत्पादन-रणनीतियों में बदलाव की मांग करती हैं। प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन चावल, जिसकी खेती में अधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है, के निर्यात के बावजूद, भूजल की सतत उपलब्धता खतरे में है। इस बीच, भारत खाद्य तेलों और दालों के आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, किसानों के हितों की रक्षा करने और संसाधनों के संरक्षण के लिए, फसल नियोजन में स्थायी कृषि पद्धतियों के साथ-साथ तिलहन और दलहन जैसी जल-कुशल फसलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृषि अनुसंधान में लागत कम करने और जोखिमों का प्रबंधन करते हुए उत्पादकता, सहनीयता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। समय पर जानकारी की बढ़ती मांग के साथ, एआई और डेटा विश्लेषण जैसे आधुनिक उपकरण वैश्विक कृषि अनुसंधान में बदलाव ला रहे हैं।

फ्लाइट में भूल से भी ना पहनकर जाएं ये चीजें, लंबे सफर में खराब हो जाएगी हालत

Travelling **दरअसल ऐसे कुछ खास किस्म के कपड़े और एक्सेसरीज हैं, जो फ्लाइट के वक्त आपको असहज कर सकते हैं। इसलिए फ्लाइट के सफर में इन्हें पहनने के लिए मना किया जाता है। चलिए जानते हैं इनके बारे में...**

• **जालंधर ब्रीज. फीचर**

क्या आपने कभी फ्लाइट में सफर किया है? अगर हां, तो क्या कभी आपने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया है। जी नहीं, पैकिंग के कपड़ों पर नहीं बल्कि आपने जो पहन रखें हैं, उन कपड़ों पर। दरअसल ये मामला स्टाइल का नहीं बल्कि आपकी सहूलियत का है। एयरपोर्ट पर जाते समय स्टाइल या आलस के मारे अगर आप कुछ भी पहनकर चले जाते हैं, तो आपको पछताना पड़ सकता है। दरअसल ऐसे कुछ खास किस्म के कपड़े और एक्सेसरीज हैं, जो फ्लाइट के वक्त आपको असहज कर सकते हैं। इसलिए फ्लाइट के सफर में इन्हें पहनने के लिए मना किया जाता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, ताकि अपने अगले सफर पर आप ये गलती ना कर बैठें।

ना पहनें ज्यादा टाइट जींस और कपड़े

फ्लाइट में ट्रैवलिंग के दौरान आपको ज्यादा टाइट जींस और बॉडी हगिंग ड्रेसेज पहनना अवॉइड करना चाहिए। लंबे समय तक ऐसे कपड़ों में आप कंफर्टेबल हो कर

बैठ भी नहीं पाएंगे और ब्लड सर्कुलेशन भी प्रभावित होगा। इसलिए बेहतर है कि ट्रैवलिंग के दौरान आप ढीले-ढाले और कंफर्टेबल क्लॉथ्स वियर करें। जींस पहननी ही है तो बॉयफ्रेंड जींस अच्छा ऑप्शन हो सकती है।

क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स

क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स देखने में बेहद स्टाइलिश लगते हैं और जाहिर है काफी कंफर्टेबल भी हैं। लेकिन फ्लाइट में यात्रा के दौरान ये आपको थोड़ा असहज भी कर सकते हैं। दरअसल विमान के एसी से निकलने वाली ठंडी हवा आपको परेशान कर सकती है। खासतौर से पेट और जांघों जैसे नाजुक हिस्से, एसी की ठंडी हवा में आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं। ऐसे में बेहतर यही है कि आप फुल कपड़े ही वियर करें।

पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक वाले कपड़े

फ्लाइट में ट्रैवल करते वक्त पॉलिएस्टर और सिंथेटिक फैब्रिक से बने कपड़े पहनना भी अवॉइड करना चाहिए। दरअसल केबिन के तापमान में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है, जिस वजह से शरीर अनकंफर्टेबल स्थिति में आ सकता है। इस दौरान ऐसे कपड़े सिलेक्ट करना बेस्ट होता है, जो शरीर को सांस लेने में मदद करें। कॉटन फैब्रिक ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट होता है।

ऐसी फुटवियर भूलकर भी ना पहनें

फ्लाइट में ट्रैवलिंग के दौरान कभी भी ऐसी फुटवियर ना पहनें जो खुली हुई हों या ऊंची एडी वाली हों। दरअसल फ्लाइट में कभी भी कोई आपातकालीन स्थिति आ सकती है। इस दौरान अगर आप ऊंची एडी वाली चप्पल, जूते या ऐसी फुटवियर पहनते हैं जो आपको भागने या चलने में परेशानी दे, तो गंभीर स्थिति भी आ सकती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप आरामदायक और सपोर्टिव जूते या सैंडल्स वियर करें।

परफ्यूम और हेवी एक्सेसरीज

फ्लाइट में सफर के दौरान आपको ज्यादा हेवी ज्वैलरी और परफ्यूम अप्लाई करने से बचना चाहिए। दरअसल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान आपको ज्वैलरी उतारनी भी पड़ सकती है और चेकिंग में आपको डिले भी हो सकता है। ज्वैलरी खोने या चोरी होने का भी काफी डर रहता है इसलिए बेहतर है कि इसे पैक कर के ले जाएं और डेस्टिनेशन पर पहन लें। वहीं अगर आप स्ट्रांग परफ्यूम लगाकर जाते हैं, तो वो फ्लाइट में बैठे अन्य यात्रियों को सिरदर्द, एलर्जी या अस्थमा ट्रिगर कर सकता है।

MINDSET

आखिर क्या सोचते हैं अमीर लोग? जानें वो 5 बातें, जो गरीब को गरीब बनाए रखती हैं

सिर्फ मेहनत और किस्मत ही नहीं बल्कि अमीर और सफल बनने के लिए जरूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट की। देखें किस तरह सेल्फ मेड अमीरों की सोच होती है बाकी सबसे अलग, जो उन्हें और अमीर बनाती हैं।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

भले ही लोग कितना कह लें कि पैसा हाथ का मैल होता है या ज्यादा पैसा बुराई की जड़ होता है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लगभग हर कोई बेशुमार दौलत कमाना चाहता है। हम अक्सर सुनते हैं कि अमीर बनना है तो खूब सारी मेहनत और भाग्य, दोनों चाहिए। बात ठीक भी है लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक चीज ऐसी है, जो अमीर इंसान को और भी ज्यादा अमीर बनाती है और गरीब आदमी वहीं का वहीं रह जाता है। वो चीज है उसकी सोच। जी हां, जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, उनके सोचने का नजरिया बाकी लोगों से बहुत अलग होता है। इसलिए तो ये मुश्किल हालातों में भी खुद को सोने सा निखार लेते हैं और बाकी लोग परिस्थिति से लड़ते-लड़ते ही थक जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर ये सफल और अमीर लोग भला सोचते कैसे हैं।

पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बनाना : मिडिल क्लास लोग अक्सर पैसा बचाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वहीं अमीरों का फोकस उस पैसे से और पैसा बनाने का होता है। मिडिल क्लास घरों में शुरू से ही बचत पर फोकस किया जाता है। इसलिए उनका पैसा अक्सर बैंक के खातों में जमा हुआ मिलता है। वहीं अमीर लोग इस पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो इन्हें शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। जाहिर है इसमें रिस्क के चांस ज्यादा होते हैं लेकिन यही रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इन सफल और अमीर लोगों को औरों से अलग बनती है।

डिग्री नहीं स्किल्स पर देते हैं ध्यान : बिल गेट्स हों या स्टीव जॉब्स, इन सभी के पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी लेकिन नई चीजें सीखते की लगन जरूर थी। इन सभी ने सेल्फ लर्निंग के जरिए नई-नई स्किल्स सीखीं और अपने काम में महारथ हासिल की। जीवन में सफल होना है तो यही फॉर्मूला अपनाना होगा। खुद को समय के साथ अपडेट करें, क्या नया चल रहा है वो जानें, नई-नई स्किल्स सीखते रहें और उनमें खुद को बेहतर बनाएं। आज के जमाने में अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो आपके लिए पैसा कमाने के ढेरों रास्ते खुल जाएंगे।

कंफर्ट जोन से निकलना है जरूरी : अमीर या सफल लोगों में अक्सर ये क्वालिटी मिलेगी कि वो लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर खुद को पुश करते हैं। रिस्क लेने, नई चीजें ट्राई करने में उन्हें एक्साइटमेंट मिलती है। कभी फेल होते हैं तो उनका एटीट्यूड एक शानदार कमबैक करने का होता है, चुपचाप बैठ जाने का नहीं। वहीं मिडिल क्लास लोग अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। दो वक्त की रोटी, मकान और एक स्टेबल नौकरी; उनकी सारी उम्र के लिए काफी होती है।

अमीर लोग हर चीज में नंबर देखते हैं और गरीब इमोशन : अमीर लोगों और मिडिल क्लास लोगों की सोच और नजरिए में ये भी एक बड़ा अंतर होता है। अमीर लोगों को हर चीज में नंबर दिखता है। अपना समय, पैसा, एनर्जी; वो हर चीज को नंबर में नापते हैं। उनके डिसीजन भी डेटा, फैक्ट, नंबर पर बेस्ड होते हैं। जबकि गरीबों के लिए इमोशन ज्यादा महत्व रखता है। वो अपने फैसले भी इसी आधार पर लेते हैं। जैसे, अगर मैं ये करूं तो कोई क्या सोचेगा, मुझे ये करना पसंद नहीं है, कुछ खराब हो गया तो। यही बातें उन्हें जीवन में अक्सर कुछ बड़ा करने से रोक देती हैं।

पैसे को ले कर नहीं रखते नेगेटिव सोच : अमीर और गरीब आदमी की सोच का अंतर ही यहीं से शुरू होता है। जहां अमीर लोग पैसे को बुराई नहीं बल्कि एंजॉय करने के साधन के रूप में देखते हैं वहीं गरीबों की सोच इसके प्रति बहुत नेगेटिव होती है। वो अक्सर इसे हाथ का मैल बताते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता या पैसा हर किसी के नसीब में कहां; ऐसी नेगेटिव बातें कहते हैं। जब पैसों को ले कर माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम ही ठीक नहीं होगा, तो इसे कमाने की मोटिवेशन और हिम्मत कहां से मिलेगी। इसलिए पैसा कमाना है तो पहले इसके लिए एक पॉजिटिव सोच रखना सीखें और इसे बुराई नहीं जिम्मेदारी की तरह देखें।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

मुरमुरा से झटपट बनाएं टेस्टी वड़ा खूब मजे से खाएंगे बच्चे और बड़े

मुरमुरा को एक हेल्दी स्नैक माना जाता है। ज्यादातर लोग इसे शाम के समय भूख लगने पर खाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुरमुरा की मदद से टेस्टी नाश्ता तैयार किया जा सकता है। यहां जानिए मुरमुरा से टेस्टी वड़ा बनाने का तरीका।

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

मुरमुरा को अलग-अलग जगहों पर अलग नाम से जाना जाता है। कुछ जगहों पर इसे लाई तो कुछ जगहों पर लईया कहा जाता है। इसे ज्यादातर लोग शाम के समय चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। अगर आप नो ऑयल वाली देसी चीजों को खाना पसंद करते हैं तो ये एक अच्छा आइटम है। इसकी मदद से टेस्टी नमकीन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर झटपट कोई नाश्ता बनाना चाहते हैं तो मुरमुरा से वड़ा तैयार करें। यहां जानते हैं मुरमुरा से वड़ा कैसे बनाएं।

मुरमुरा वड़ा के लिए सामाग्री

- 2 कप मुरमुरा
- 1 इंच कटा हुआ अदरक
- 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्च
- 10 से 15 करी पत्ता
- 1 छोटा चम्मच जीरा
- स्वादानुसार नमक
- 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
- 1/2 कप चावल का आटा
- 3 बड़े चम्मच दही
- फ्रेश धनिया पत्ती
- तलने के लिए तेल

मुरमुरा वड़ा कैसे बनाएं

मुरमुरा वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा कटोरा लें और उसमें बताई गई मात्रा में मुरमुरा लें। फिर इसमें पानी डालें और कुछ देर के लिए भिगो दें। फिर मुरमुरा को छान लें। जब सारा पानी निकल जाए तो एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करें और फिर इसमें चावल का आटा, दही, हरी मिर्ची, अदरक, करी पत्ता, जीरा, नमक, काली मिर्च, धनिया पत्ती डालें और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। कुछ देर के लिए रखें और फिर हाथों पर तेल लगाएं। अब थोड़ा-थोड़ा लेकर वड़ा तैयार करें। सभी वड़े तैयार होने के बाद एक कढ़ाई में तेल गर्म करें। अच्छी तरह गर्म हो जाने के बाद लो से मीडियम आंच पर सभी वड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक तलें। अब क्रिस्पी वड़ों को चटनी के साथ सर्व करें। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रही हैं तो हरी मिर्च को अवॉइड करें।

जंक फूड का शौक छीन सकता है आंखों की रोशनी, बरतें ये सावधानी

जालंधर ब्रीज (फीचर) . आजकल बच्चे हों या बड़े, लोग घर के बने पोष्टिक भोजन को छोड़कर बर्गर, पिज्जा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स जैसे जंक फूड्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जंक फूड का अधिक सेवन पाचन से जुड़ी कई समस्याओं का कारण बनता है, यह बात तो ज्यादातर लोगों को पता होती है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा जंक फूड का सेवन बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंचाकर उनकी आंखों की रोशनी तक छीन सकता है। जी हां, हाल की एक रिसर्च में सामने आया है कि जंक फूड्स का अधिक सेवन बच्चों की आंखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक इस आदत को नजरअंदाज करने पर यह अंधेपन तक का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कैसे आपके बच्चे की आंखों का दुश्मन है जंक फूड और क्या हैं बचाव के उपाय।

बच्चे की आंखों पर कैसे बुरा असर डालता है जंक फूड : डॉक्टर्स के अनुसार जंक फूड में आंखों के लिए जरूरी विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और जिंक जैसे पोषक तत्वों की कमी होती है। इस तरह के फूड का अधिक सेवन करने से बच्चे की आंखों की कोशिकाओं को पोषण नहीं मिल पाता है और उसे आंखों में ड्राईनेस, धुंधलापन, आंखों में जलन, कमजोर रोशनी जैसी समस्याएं होनी शुरू हो सकती हैं। बता दें, ओमेगा-3 और विटामिन ए की कमी से रेटिना की कोशिकाएं कमजोर होने लगती हैं जबकि पौष्टिक तत्वों की कमी लंबे समय तक बने रहने से आंखों की नसें डैमेज तक हो सकती हैं, जिससे अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है।

बच्चे की आंखों की सेहत के लिए बरतें ये सावधानियां

• बच्चे को जंक फूड की जगह संतुलित आहार खाने की आदत डालें। • बच्चे की डाइट में गाजर, पालक, दूध, अंडा, अखरोट, और मछली जैसी चीजें शामिल करें। • संतुलित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर आंखों की रोशनी को खराब होने से बचाया जा सकता है। • आंखों के डॉक्टर से अपने बच्चे की आंखों की नियमित जांच करवाएं। • नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर आंखों के व्यायाम करें।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

नींद डिस्टर्बेंस से धीरे-धीरे शरीर के कई हिस्से होने लगते हैं खराब

Health **रोजाना अगर कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते हैं तो ये आपके हेल्थ को पूरी तरह से बिगाड़ने लगती है। जिससे ब्रेन से लेकर गट हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और शरीर के ये 6 हिस्से प्रभावित होते हैं।**

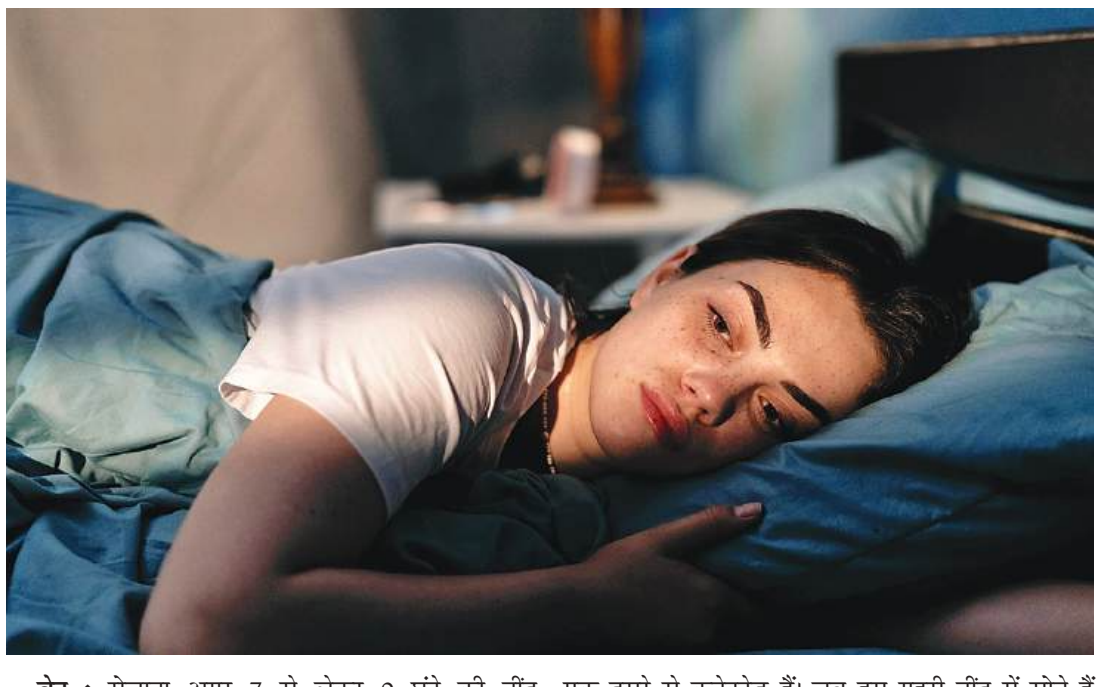

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

हेल्दी फूड और वर्कआउट की तरह ही नींद भी बहुत जरूरी है। लेकिन काफी सारे लोग पर्याप्त नींद को काम और दूसरी चीजों की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन अगर आप लगातार कई दिनों तक या कई महीनों तक पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते यानी आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ये गंभीर रूप से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। एचटी लाइफस्टाइल को पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताया कि स्लीप बॉडी के फंक्शन से इंटरकनेक्टेड है और अगर नींद पूरी नहीं होती तो ये बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। अगर लंबे टाइम तक कोई इंसान 7 से लेकर 9 घंटे की नींद पूरी नहीं करता है तो इससे मेंटली और फिजकली इन चीजों पर असर पड़ता है।

स्किन : जब इंसान का माइंड रिलैक्स होता है तो उस वक्त स्किन अपना रिजनरेशन करती है। जिससे स्किन को हील होने और डैमेज को ठीक करने में मदद मिलती है और स्किन पर ग्लो दिखता है। अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती तो डल स्किन, डार्क सर्कल, फाइन लाइंस और प्रीमेच्योर एजिंग दिखना शुरू हो जाते हैं। जिसका कारण कॉर्टिसोल लेवल का बढ़ना और कोलेजन प्रोडक्शन का घटना है। यहीं नहीं पूअर स्लीप क्वालिट एक्ने और स्किन पर एक्जिमा, सोरायिस जैसी बीमारियों को बढ़ा देती है।

दिल की सेहत का है सीधा कनेक्शन : गहरी नींद में इंसान जब होता है तो ब्लड प्रेशर रेगुले होता है। हार्ट रेट नॉर्मल होती है और कॉर्डियोवस्कुलर सिस्टम को मौका मिलता है आराम से काम करने का। जब इंसान की नींद बार-बार डिस्टर्ब होती है हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इररेगुलर हार्ट रिदम का रिस्क बढ़ जाता है।

गट हेल्थ पर भी होता है असर : आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया ही हैं जो हमे स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जब इंसान ठीक से नहीं सोता और उसकी नींद पूरी नहीं होती है तो गट माइक्रोबियम का कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ना शुरू कर देते हैं।

ब्रेन : रोजाना अगर 7 से लेकर 9 घंटे की नींद नहीं पूरी होती है तो इसका सीधा असर दिमाग पर होता है। स्लीप क्वालिटी मूड और इमोशन और स्टेबल करने में मदद करती है। वहीं नींद पूरी ना होने से एंजायटी, इरैटिबिलिटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस की समस्या बढ़ जाती है।

इम्यूनिटी बिगड़ जाती है : नींद और बॉडी फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब हम गहरी नींद में सोते हैं तो बॉडी में साइटोकाइन्स नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस से लड़ता है। खराब नींद इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है।

डिस्क्लेमर : यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।

भारतीय हथकरघा के लिए नवाचार और स्थायित्व के साथ भविष्य बुनना

जालंधर ब्रीज . हथकरघा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और 3.5 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है। स्थानीय बुनकरों द्वारा नैतिक रूप से निर्मित हथकरघा और दस्तकारी वस्त्र, बड़े पैमाने पर उत्पादित फास्ट फैशन का एक सार्थक विकल्प प्रस्तुत करते हैं। ऐसा करके, वे भारत की समृद्ध विरासत को आधुनिक विश्व के लिए एक व्यापक स्थिरता की कहानी में शामिल करते हैं।

टिकाऊ वस्त्र इको-सिस्टम के निर्माण के लिए ग्रामीण हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टरों को सहायता देना महत्वपूर्ण है। ये क्लस्टर भारतीय शिल्पकला की उन जीवंत परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें परिवारों और समुदायों द्वारा पीढ़ियों से कायम रखा गया है। निजी क्षेत्र और सामाजिक उद्यमों ने इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में सराहनीय भूमिका निभाई है। उनका कार्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के साथ नवाचार, स्थानीय स्रोत, रि-साईकिलिंग और अप-साईकिलिंग, तथा पारंपरिक प्रथाओं के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने तक फैला हुआ है। ये प्रयास सहयोग के माध्यम से कारीगर समुदायों को सशक्त बनाने, शिल्पकारों और डिजाइनरों के बीच साझेदारी बनाने, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने और कारीगरों को वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 और अमेरिका के सांता फे में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला बाजार जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भारतीय शिल्पकारों की हालिया भागीदारी उनकी अनुकूलनशीलता और वैश्विक अपील को दर्शाती है।

भारत सरकार अनेक योजनाओं और पहलों के माध्यम से वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र (टेक्सटाइल इको-सिस्टम) का समर्थन करती है। इनमें कच्चे माल की खरीद, करघों और सहायक उपकरणों आदि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रम तथा पारंपरिक हथकरघों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु मार्केटिंग प्रयास शामिल हैं। पर्यावरण-अनुकूल और सर्कुलर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने, जैविक कच्चे माल तक पहुँच में सुधार लाने और नैतिक प्रथाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी पहलों ने हथकरघा बुनकरों के लिए अवसरों का काफी विस्तार किया है। 'कौशल भारत' और 'डिजिटल भारत' जैसे अन्य कार्यक्रम कारीगरों को अपने कौशल को अपग्रेड करने और अपने कार्यस्थलों से सीधे बड़े बाजारों तक पहुंचने में सक्षम बना रहे हैं।

इस क्षेत्र के विकास को बनाए रखने के लिए हथकरघा परंपराओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण भी समान रूप से आवश्यक है। वस्त्र मंत्रालय के नेतृत्व में डिजिटल संग्रह, भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, पारंपरिक और समकालीन ज्ञान दोनों को संग्रहित करके इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह मंच अनुसंधान डेटा, डिजाइनर और कारीगर प्रोफाइल, एक वर्चुअल संग्रहालय और डिजिटल प्रदर्शनियां उपलब्ध कराता है, जिससे यह विद्वानों, शिक्षार्थियों और शिल्प उत्साही लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन बन जाता है।

गिरिराज सिंह
(केंद्रीय वस्त्र मंत्री, भारत सरकार)

हथकरघा क्षेत्र को अधिक लक्ष्य-उन्मुख और लाभदायक बनाने के लिए व्यवसाय-केंद्रित रणनीति आवश्यक है। को-ऑप्टेक्स, बोयानिका अथवा टाटा ट्रस्ट द्वारा अन्तरान जैसे हथकरघा मार्केटिंग संगठनों की केस स्टडी से पता चलता है कि व्यवस्थित योजना, चाहे वह समितियों, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के माध्यम से हो अथवा गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ सहयोग के माध्यम से हो, हथकरघा बुनकरों की आय और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है।

इसे हासिल करने के कई तरीके हैं। पारंपरिक और आधुनिक, दोनों बाज़ारों के लिए नए डिज़ाइन विकसित करने के साथ-साथ पारंपरिक डिज़ाइनों को पुनर्जीवित करना, खासकर थीम-आधारित प्रदर्शनियों के ज़रिए, ग्राहकों को शिक्षित करने और माँग बढ़ाने में मदद कर सकता है। अंगवस्त्रम, वेष्टी और मुंडू जैसे उत्पादों को भी प्रासंगिक बने रहने के लिए विचारशील डिजाइन नवाचार की आवश्यकता होती है। वर्तमान आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 22% हथकरघा बुनकर साड़ियां बनाते हैं और 19% अंगवस्त्रम और इसी तरह के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे 59% ऐसे बुनकर बचते हैं जिन्हें घरेलू साज-सज्जा और वस्त्र सामग्री की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित और सक्रिय किया जा सकता है। आधुनिक रुचियों के अनुरूप ढलते हुए, भारतीय हथकरघा को परिभाषित करने वाले अद्वितीय क्षेत्रीय कौशल और तकनीकों को संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। जैविक फाइबर, प्राकृतिक रंगों और टिकाऊ सामग्रियों के उपयोग से हथकरघा उत्पादों का मूल्य और आकर्षण और अधिक बढ़ सकता है।

वस्त्र मंत्रालय संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार जैसे पुरस्कारों के माध्यम से बुनकरों के योगदान को सक्रिय रूप से मान्यता प्रदान कर रहा है और उन्हें पुरस्कृत कर रहा है। हाल के वर्षों में, नई श्रेणियां शुरू की गई हैं, जैसे कि महिला बुनकरों, जनजातीय कारीगरों, दिव्यांग बुनकरों, नवोन्मेषी उत्पादक समूहों और हथकरघा के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने वाले डिजाइनरों के लिए पुरस्कार। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि युवाओं को युवा बुनकर पुरस्कार भी दिया जाता है, जोकि 30 वर्ष से कम आयु के ऐसे कारीगरों को दिया जाता है, जिन्होंने पारंपरिक तकनीकों में निपुणता प्राप्त कर ली है तथा नवाचार अथवा उद्यमिता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ये पुरस्कार न केवल प्रतिष्ठित हैं बल्कि पारदर्शी और लोकतांत्रिक भी हैं, तथा इनके साथ नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं। संत कबीर, राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 8,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य हथकरघा के क्षेत्र में नवाचार, विशेष रूप से ऐसी तकनीकों और सौंदर्यबोध को बढ़ावा देना है, जिनकी मशीनों अथवा पावरलूमों द्वारा नकल नहीं की जा सकती है।

भारतीय हथकरघा उद्योग का स्थायित्व बनाए रखने के लिए परंपरा और नवाचार दोनों को अपनाने की आवश्यकता है। भारत कपास, रेशम, ऊन, जूट और नारियल के रेशों जैसे प्राकृतिक फाइबर से समृद्ध है, और यहाँ बाँस, केले के फाइबर, हेम्प और मिल्कवीड जैसी नई सामग्रियों की खोज तेज़ी से हो रही है। कृषि अपशिष्ट की एक बड़ी मात्रा भी अभी तक पूरी तरह से उपयोग में नहीं आ पाई है। इस प्रचुरता के बावजूद, वास्तव में टिकाऊ उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर यार्न और वस्त्र प्रसंस्करण को मजबूत करने की अभी भी आवश्यकता है।

वस्त्र क्षेत्र में उद्यमों के सर्कुलर उत्पादन में तेजी आ रही है। वर्तमान समय में भारत की गहन भौतिक संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ रही है, यह केवल यार्न और फैब्रिक में ही नहीं, बल्कि परिधानों के सहायक उपकरणों में भी बढ रही है, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है। बचे हुए कपड़ों और धागों का उपयोग करके बनाए गए पुनर्चक्रित संग्रह लोकप्रिय हो रहे हैं, जो पारंपरिक, टिकाऊ प्रथाओं के पुनरुद्धार में योगदान दे रहे हैं। यह आंदोलन पर्यावरण के प्रति जागरूक फैशन की ओर एक व्यापक वैश्विक बदलाव को दर्शाता है।

आज, तेज़ी से बढ़ते शहरी प्रवास और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे के साथ, पारंपरिक बुनकर की अपने करघे पर भूमिका प्रतीकात्मक से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है, अब यह हरित तकनीक और सांस्कृतिक संरक्षण का एक सशक्त उदाहरण बन गई है। भारत की हथकरघा विरासत एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करती है जो पर्यावरण और शिल्प से जुड़े लोगों का सम्मान करती है और देश को ज़िम्मेदार एवं नैतिक फ़ैशन के क्षेत्र में अग्रणी बनाती है।

पीएम-किसान : किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के रूपांतरण का भारत का वैश्विक खाका

जालंधर ब्रीज . समावेशी विकास और ग्रामीण समृद्धि के सफर में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना, भारत सरकार की एक अग्रणी पहल के रूप में उभर कर सामने आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई, इस पहल ने लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है और पूरी तरह से डिजिटल, कुशल एवं पारदर्शी प्रणाली के जरिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के एक वैश्विक मॉडल के रूप में खुद को स्थापित किया है।

प्रमोद मेहरदा
डॉ. प्रमोद मेहरदा, अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार

अरिंदम मोदक
सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष समर्थन के जरिए किसानों का सशक्तिकरण : मूल रूप से, पीएम-किसान योजना पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करती है। यह सहायता राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के जरिए 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस सुव्यवस्थित एवं तकनीक-संचालित कदम से बिचौलियों की भूमिका, लाभ मिलने में होने वाली देरी और त्रुटि की गुंजाइश खत्म होती है और एक-एक पाई इच्छित लाभार्थी तक पहुंचना सुनिश्चित होता है। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब-तक, कुल 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। इस प्रकार, पीएम-किसान दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल रूप से क्रियान्वित नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में से एक बन गया है। आंकड़ों से परे, यह कदम सब्सिडी से हटकर सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ने संबंधी एक बदलाव का प्रतीक है। बात चाहे बीज की हो या उपकरण या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की, इस योजना से किसानों को यह तय करने की आजादी मिलती है कि वे इस सहायता का सबसे बेहतर इस्तेमाल कैसे करें।

भारत के छोटे किसानों के हित में एक परिवर्तनकारी कदम : दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसानों के लिए ये लाभ बुवाई या कटाई के मौसम में एक अहम आर्थिक सेतु का काम करते हैं। ये लाभ अल्पकालिक नकदी प्रवाह के तनाव को कम करते हैं, अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी लाते हैं और संकट के समय एक सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। वित्तीय सहायता से कहीं बढ़कर, पीएम-किसान योजना समावेशिता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक भागीदार के रूप में किसान की मान्यता का प्रतीक है।

डिजिटल शासन की श्रेष्ठता : पीएम-किसान की सफलता का श्रेय भारत के मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे को जाता है। जेएएम की तिकड़ी - जन धन बैंक खाते, आधार बायोमेट्रिक पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी - ने बड़े पैमाने पर लाभ के निर्बाध वितरण को संभव बनाया है। स्व-पंजीकरण से लेकर भूमि स्वामित्व के सत्यापन और डीबीटी द्वारा समर्थ भुगतान तक, इस पूरी योजना का जीवनचक्र डिजिटल है। राज्य सरकारों के सहयोग से, पीएम-किसान डिजिटल रूप से समन्वित तथा एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से पहुंचने वाले शासन के एक बेहतरीन मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसने विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों, लाभार्थियों के डेटाबेस और भुगतान प्रणालियों को सफलतापूर्वक समन्वित किया है और इससे दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में किसान-केन्द्रित एक उत्तम संरचना का निर्माण हुआ है।

पीएम किसान ने कृषि से जुड़े इकोसिस्टम में किसान ई-मित्र वॉयस-आधारित चैटबॉट और एग्री स्टैक जैसी नवीन परियोजनाओं को भी प्रेरित किया है। एग्रीस्टैक व्यक्तिगत, समय पर और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार है, जिससे भारतीय कृषि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।

वैश्विक मानकों की स्थापना : दुनिया भर में, प्रत्यक्ष लाभ कार्यक्रमों को गरीबी उन्मूलन के कारगर साधनों के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है। फिर भी, पीएम-किसान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं – इसका विशाल आकार, गति और डिजिटल विश्वसनीयता इसे बिखरी हुई कृषि सहायता प्रणालियों में सुधार के लिए प्रयासरत देशों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनाती है। आईएफपीआरआई, एफएओ, आईसीएआर और आईसीआरआईएसएटी जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने छोटे किसानों की आय बढ़ाने, ऋण की सुलभता में सुधार, असमानता को कम करने और आधुनिक कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में पीएम किसान की भूमिका पर प्रकाश डाला है। कई देशों में जारी सशर्त हस्तांतरण के उलट, इसका विश्वास-आधारित व बिना शर्त वाला दृष्टिकोण, सहभागी एवं सम्मान-आधारित कल्याणकारी वितरण की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

ग्रामीण विकास को गति देना : पीएम-किसान का सकारात्मक प्रभाव केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों तक ही सीमित नहीं है। इसके तहत होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाह ने ग्रामीण बाजारों को पुनर्जीवित किया है, कृषि-उत्पादों की मांग को प्रोत्साहित किया है और घरेलू उपभोग के पैटर्न को मजबूत किया है। इसने महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर उन मामलों में जहां बैंक खाते संयुक्त रूप से खोले जाते हैं।

इसके अलावा, यह एक समग्र और परस्पर संबद्ध ग्रामीण विकास इकोसिस्टम का निर्माण करके मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा योजना और ई-नाम जैसी अन्य प्रमुख योजनाओं का पूरक है। किसानों के लिए एक पेंशन योजना, पीएम-किसान मानधन योजना के साथ इसका एकीकरण, भारत के कृषि कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

सुनहरे भविष्य का एक दृष्टिकोण: दृढ़ता, समानता और स्थिरता : पीएम-किसान एक वित्तीय सहायता तंत्र से कहीं बढ़कर है। यह भारत सरकार के किसानों के नेतृत्व वाले विकास का एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। अधिकार से सशक्तिकरण की ओर, सहायता से स्वायत्तता की ओर स्थानांतरित होकर, यह राज्य और किसान के बीच अनुबंध को नए सिरे से परिभाषित करता है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है, ऐसे में पीएम-किसान जैसी पहल समावेशी प्रगति की नींव रखती है। उन्नत तकनीकों के निरंतर एकीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति दृढ़ता, स्थिरता और सटीक कृषि पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, यह योजना बदलाव की दिशा में एक बेहद शक्तिशाली कदम के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है। पीएम-किसान विश्वास, तकनीक और परिवर्तन की कहानी है। यह दुनिया के लिए भारत का योगदान है। यह योजना एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक दूरदर्शी नीति, डिजिटल नवाचार और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ मिलकर, लाखों लोगों को सशक्त बना सकती है और 21वीं सदी के शासन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती है।

सीयू पंजाब में दिशा आईपीईवी ड्राइव का आयोजन- युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर हेतु किया प्रेरित

जालंधर ब्रीज . पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा ने भारतीय वायुसेना के सहयोग से मंगलवार, 5 अगस्त 2025 को दिशा इंडक्शन पब्लिसिटी एग्ज़ीबिशन व्हीकल (आईपीईवी) ड्राइव-16 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम वायुसेना मुख्यालय के दिशा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य युवाओं को भारतीय वायुसेना में उपलब्ध रोमांचक करियर विकल्पों के बारे में जागरूक करना और उन्हें सम्मान, अनुशासन एवं राष्ट्र सेवा से युक्त जीवन के लिए वायुसेना से जुड़ने हेतु प्रेरित करना था।

इस अवसर पर वायुसेना मुख्यालय के दिशा प्रकोष्ठ से विंग कमांडर एम. निशांत कुलश्रेष्ठ, स्क्वाड्रन लीडर अभिमन्यु कादियान, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुरशरण तथा वायुसेना स्टेशन भिसियाना से विंग कमांडर श्वेता पांडे अपनी टीम सहित विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचे। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया और वायुसेना में करियर की संभावनाओं पर विस्तारपूर्वक मार्गदर्शन प्रदान किया।कार्यक्रम के शुभारंभ पर कुलपति प्रो. राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत को योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक विरासत के कारण 'सॉफ्ट पावर' के रूप में वैश्विक स्तर पर सराहा जाता है, लेकिन विकसित भारत की दिशा में अग्रसर होने के लिए देश को 'हार्ड पावर' के रूप में भी स्थापित होना होगा।

इस दिशा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को सशस्त्र बलों में सेवा का विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया, जहाँ कर्तव्य, गरिमा और देशसेवा का संगम होता है।कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण था अत्याधुनिक तकनीक से युक्त इंडक्शन पब्लिसिटी एग्ज़ीबिशन व्हीकल (आईपीईवी), जिसमें उड़ान सिम्युलेटर, ग्लासट्रॉन हेडसेट, इंटरैक्टिव टचस्क्रीन कियोस्क, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेज़, विमान मॉडल, जी-सूट और एलईडी डिस्प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। विद्यार्थियों ने इन तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव लिया और भारतीय वायुसेना की कार्यप्रणाली को बेहतर ढंग से समझा।विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों ने इस दिशा-आईपीईवी ड्राइव में उत्साहपूर्वक भाग लिया। उन्होंने वायुसेना अधिकारियों से बातचीत कर वायुसेना में प्रवेश की प्रक्रियाओं—जैसे एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (एएफसीएटी) तथा फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी) और ग्राउंड ड्यूटी (गैर-तकनीकी) शाखाओं में उपलब्ध करियर विकल्पों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

कार्यक्रम के समापन पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. संजीव ठाकुर ने दिशा प्रकोष्ठ और वायुसेना स्टेशन, भिसियाना की टीम का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक पहल को सीयू पंजाब परिसर तक पहुँचाया। गौरतलब है कि इस दिशा-आईपीईवी अभियान को 28 जुलाई 2025 को विजय चौक, नई दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, और यह आने वाले दिनों में पंजाब के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया जाएगा।

केंद्र ने राज्यों से स्थानीय स्तर पर वैश्विक फिल्म निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए इंडिया सिने हब पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया

जालंधर ब्रीज . सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 अगस्त, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क सचिवों के साथ एक उच्च-स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य जनसंचार में केंद्र-राज्य समन्वय को मज़बूत करना, प्रेस सेवा पोर्टल और इंडिया सिने हब का पूर्ण कार्यान्वयन और कार्यक्षमता सुनिश्चित करना, और फिल्म अवसंरचना के विकास और विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक अवसरों की खोज करना था।

मीडिया सुधार और भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का विस्तार : सम्मेलन को संबोधित करते हुए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने कहा कि भारतीय सिनेमा हब पोर्टल को एक एकीकृत सिंगल-विंडो प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है, जो पूरे भारत में फिल्म निर्माण अनुमतियों और सेवाओं तक सुगम पहुँच प्रदान करता है। जीआईएस सुविधाओं और सामान्य प्रपत्रों के साथ, यह व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की फिल्म-अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करता है।

मंत्री महोदय ने कम लागत वाले थिएटरों के माध्यम से महिलाओं और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने वाली जमीनी स्तर की सिनेमा पहलों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने वेव्स 2025 और आईएफएफआई गोवा जैसे प्रमुख वैश्विक आयोजनों पर ज़ोर दिया, जो वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करेंगे, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे, दुनिया भर में सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देंगे और भविष्य के रचनात्मक दिमागों को सशक्त बनाएंगे।

उन्होंने हाल ही में शुरू किए गए भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी) पर विशेष जोर दिया, जिसका उद्देश्य युवाओं को एनीमेशन, गेमिंग, संगीत और अन्य रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल प्रदान करना है। उन्होंने देश में सृजनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

मीडिया उन्नति के लिए सहयोगात्मक शासन : कार्यक्रम के दौरान, सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने प्रभावी संचार और मीडिया विकास में केंद्र-राज्य सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर दिया। उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स, स्थानीय मीडिया के उदय और जिला-स्तरीय सूचना एवं जनसंपर्क व्यवस्थाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने सभी राज्यों से सुचारू प्रकाशन प्रक्रियाओं के लिए प्रेस सेवा पोर्टल के साथ जुड़ने का आग्रह किया और राज्यों के मीडिया विभागों में असंबद्ध ज़िम्मेदारियों पर चिंता व्यक्त की।

डॉ. एल. मुरुगन
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री

धीरेन्द्र ओझा
महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)

संजय जाजू
सूचना एवं प्रसारण सचिव

जाजू ने सिनेमा और कंटेंट निर्माण की आर्थिक संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला और महानगरों से आगे विस्तार करने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और रचनाकारों को कंटेंट से कमाई करने में सक्षम बनाने के लिए इंडिया सिने हब जैसी पहल शुरू की गई। उन्होंने वेव्स शिखर सम्मेलन को एक वैश्विक आंदोलन बताया और मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र में संवाद और सहयोग को गहरा करने के लिए गोवा में आईएफएफआई के दौरान एक रेडियो कॉन्क्लेव की योजना की घोषणा की।

प्रमुख फोकस क्षेत्र:

सम्मेलन का एक प्रमुख फोकस क्षेत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को प्रेस सेवा पोर्टल के बारे में जागरूक करना और उन्हें इससे जोड़ना था। प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 के अंतर्गत भारत के प्रेस महापंजीयक द्वारा विकसित यह पोर्टल एक एकल-खिड़की डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म था जो पत्रिकाओं से संबंधित पंजीकरण और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुगम बनाता था।

एक अन्य प्रमुख विशेषता, संशोधित इंडिया सिने हब पोर्टल पर ज़ोर देना था, जो 28 जून 2024 को लाइव हो गया। यह पोर्टल अब पूरे भारत में फिल्म-संबंधी सुविधाओं के लिए एकल-खिड़की प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर फिल्मांकन अनुमतियों, प्रोत्साहनों और संसाधन मानचित्रण तक एकीकृत पहुँच प्रदान करता है। सात राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही पूर्ण एकीकरण पूरा कर लिया है, जबकि इक्कीस राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों को एक सामान्य आवेदन पत्र के माध्यम से शामिल किया गया है।

इंडिया सिने हब पोर्टल ने जीआईएस-आधारित लोकेशन मैपिंग, उद्योग जगत के पेशेवरों से क्राउडसोर्स्ड कंटेंट और फिल्मांकन, गैर-फिल्मांकन और प्रोत्साहनों के लिए विभेदित वर्कफ़्लो का समर्थन किया। सम्मेलन में आवेदनों के प्रसंस्करण और वैश्विक फिल्मांकन स्थल के रूप में भारत की अपील को बेहतर बनाने के लिए सत्यापित डेटा के योगदान पर चर्चा की गई।

सम्मेलन में वंचित क्षेत्रों में कम लागत वाले सिनेमा हॉलों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई। भारत दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़िल्में बनाने वाले देशों में से एक होने के बावजूद, सिनेमा के बुनियादी ढाँचे तक पहुँच असमान बनी हुई है। मंत्रालय ने टियर-3 और टियर-4 शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों की सेवा के लिए मॉड्यूलर और मोबाइल सिनेमा मॉडल विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

सम्मेलन में इस बात पर चर्चा की गई कि जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके कम स्क्रीन घनत्व वाले क्षेत्रों की पहचान कैसे की जाए, मौजूदा सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का पुनः उपयोग कैसे किया जाए, एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से लाइसेंसिंग को सरल कैसे बनाया जाए, तथा किफायती सिनेमा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कर और भूमि नीति प्रोत्साहन कैसे प्रदान किए जाएं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) और वेव्स बाज़ार जैसे प्रमुख फिल्म और कंटेंट प्लेटफॉर्म में भागीदारी पर भी विचार-विमर्श किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने फिल्मांकन स्थलों को प्रदर्शित करने, क्षेत्रीय प्रोत्साहनों को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 55वें आईएफएफआई में 114 देशों ने भाग लिया और इससे जुड़े वेव्स बाज़ार ने 30 देशों के 2,000 से ज़्यादा उद्योग प्रतिनिधियों की मेज़बानी की। राज्य समर्पित मंडप स्थापित करके, भारतीय पैनोरमा में प्रविष्टियों को सुगम बनाकर और रचनात्मक प्रतिभाओं को वैश्विक प्रदर्शन के लिए नामांकित करके इन अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

चर्चा का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र भारत की लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था का विकास था। सम्मेलन में राज्यों के साथ आयोजनों के लिए मौजूदा खेल और सांस्कृतिक बुनियादी ढाँचे के उपयोग, इंडिया सिने हब में अनुमति प्रक्रिया को एकीकृत करने, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और लाइव मनोरंजन बुनियादी ढाँचे में निवेश के लिए नीतिगत और वित्तीय सहायता स्थापित करने पर विचार-विमर्श किया गया।

इस उच्च स्तरीय बातचीत का उद्देश्य मीडिया, संचार और रचनात्मक अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग को सुदृढ़ करना था, जिससे डिजिटल रूप से सशक्त और सांस्कृतिक रूप से जीवंत समाज के रूप में भारत की प्रगति में योगदान मिल सके।

नगर निगम के दफ़्तर में ही गंदगी का आलम, कैसे सजेगा शहर?

नगर निगम जालंधर के प्रवेश द्वार पर बिखरी पड़ी बजरी।

इमारत की छत पर लगा खराब हो चुकी कुर्सियों व अन्य सामान का ढेर।

छत की जर्जर हालत बयां करती तस्वीर।

• **जालंधर ब्रीज** . विशेष रिपोर्टर

शहर को सुंदर और साफ-सुथरा बनाने का सपना दिखाने वाला नगर निगम जालंधर अपने ही कार्यालय की हालत नहीं सुधार पा रहा। ऐसे में यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि यह पूरे शहर की देखभाल करेगा?

स्वास्थ्य शाखा में बैठे कुछ अधिकारी लैपटॉप पर आँकड़े दिखा कर आईएएस अफसरों को गुमराह करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर वे अपने ही ऑफिस की छत और चारदीवारी की ओर नज़र डालें तो सच्चाई सामने आ जाएगी। जिस बिल्डिंग में मेयर, कमिश्नर और पूरा स्टाफ बैठता है, उसकी छत पर सालों से टूटे-फूटे सामान का ढेर लगा हुआ है।

कई जगहों से दीवारें जर्जर हो चुकी हैं और छतों में दरारें पड़ी हुई हैं। यह स्थिति अपने आप में किसी बड़े हादसे को न्योता दे रही है। यहां तक कि नगर निगम के मुख्य गेट के बाहर सड़क पर बिखरी बजरी भी खतरे को दावत दे रही है, जिससे कभी भी कोई दोपहिया वाहन फिसल सकता है और किसी कर्मचारी की जान भी जा सकती है।

नगर निगम प्रशासन बड़े-बड़े दावे करता है, लेकिन जब कोई नागरिक फोन करता है तो अधिकारी कहते हैं कि जिस जगह की शिकायत है उसकी फोटो भेजो। अफसोस की बात यह है कि अपने ही ऑफिस को देखने की भी उन्हें फुर्सत नहीं।

ऐसा लगता है कि काम होना या ना होना प्रशासनिक अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर करता है। यह सीधे तौर पर उनकी कार्यशैली और लापरवाही को उजागर करता है। सरकार के बड़े-बड़े वादों की पोल तब खुलती है जब कोई हादसा हो जाता है, लेकिन तब भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।

क्या इसी को कहते हैं "सेवा और सच्चाई के साथ काम करने वाला प्रशासन"? या फिर यह केवल कागज़ी दावों का एक और उदाहरण है?

भयानक हादसे को न्यौता दे रही पानी में बिखरी पड़ी तारें।

सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश; 7 पिस्तौल समेत चार गिरफ्तार

प्रदेश में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई कर रहे थे गिरफ्तार किए गए आरोपी : डीजीपी

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/अमृतसर

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हो रही हथियार तस्करी में शामिल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सात अति-आधुनिक पिस्तौल बरामद किए। यह जानकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने वीरवार को यहाँ दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अमृतसर के गांव दाओके के रहने वाले आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश (20), अमृतसर के गांव बाघा कलां के निवासी रमनप्रीत सिंह (23), फिरोज़पुर के गांव सुर सिंह के निवासी प्रताप सिंह (25) और अमृतसर के देबी वाला बाज़ार के निवासी सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल (25) के रूप में हुई है। बरामद किए गए पिस्तौलों में दो 9एमएम पीएक्स5, दो 9एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और भारत-पाक सीमा के नजदीक अवैध हथियारों की खेप प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी सरहदी गांवों से काम कर रहे थे और प्रदेश में गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करते थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए और जांच की जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क और इसके संपर्कों का पता लगाया जा सके। पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस से पहले बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के मद्देनज़र, पुलिस टीमों ने खास खुफिया सूचना पर कार्रवाई करते हुए, थाना छेहरटा अधीन आने वाले क्षेत्र से आकाश और रमन को गिरफ्तार किया है और उनसे चार पिस्तौल—दो पीएक्स5 9 एमएम और दो .30 बोर पिस्तौल बरामद किए गए हैं।

इसके बाद उनके दो साथियों प्रताप सिंह और सरबजीत सिंह उर्फ बब्बल को भी उसी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से तीन और पिस्तौल बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी आकाश अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक रहता है और वह रमन के साथ मिलकर सीमा पार से हथियारों की खेप प्राप्त करता था, जबकि उनके साथी सरबजीत और प्रताप हथियार सप्लाई कार्यों के लिए तालमेल और प्रबंधन करते थे। उन्होंने कहा कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में बड़ी आपराधिक वारदात टल गई है।

उच्च न्यायालय ने रणजीत सिंह गिल की याचिका पर लिया संज्ञान

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में आज रणजीत सिंह गिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है और मंगलवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। गिल की ओर से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता एनके वर्मा ने अदालत को बताया कि सरकार की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि रणजीत सिंह गिल को वर्ष 2021 की एक एफआईआर में केवल गवाह के तौर पर बुलाया गया था और उन्हें किसी भी केस में आरोपी नहीं बनाया गया है।

वर्मा ने यह भी कहा कि गिल की प्रॉपर्टियों पर विजिलेंस द्वारा की गई रेड पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित थी, जबकि किसी भी मामले में उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। उन्होंने यह कार्रवाई गिल की छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास बताया। मालूम हो कि रणजीत सिंह गिल ने 18 जुलाई को शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफ़ा दे दिया था और 1 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे।

कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में विभिन्न स्थानों पर चलाया विशेष अभियान, 16 गिरफ्तार

46 ग्राम हेरोइन समेत 61 नशीली गोलियां बरामद, कार और मोटरसाइकिल भी ज़ब्त

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

'युद्ध नशे के विरुद्ध' अभियान के तहत, कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने शहर में विभिन्न स्थानों पर एक विशेष अभियान चलाया, जिसके दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं नशीले पदार्थ, अवैध शराब और वाहन बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने बताया कि कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पुलिस थानों द्वारा यह अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप 4 ड्रग सप्लायर/तस्करों सहित नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत 8 मामले दर्ज किए गए और 46 ग्राम हेरोइन समेत 61 नशीली गोलियां बरामद की गई। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस ने एक कार और एक मोटरसाइकिल भी ज़ब्त की है। इसके अलावा, पुलिस ने 36000 मिलीलीटर अवैध शराब भी ज़ब्त की है और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर इसमें शामिल एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है।

इसके अलावा, 6 नशा पीड़ितों को पुनर्वास के लिए नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि जालंधर पुलिस नशा तस्करों की पहचान और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए शहर स्तर पर सक्रिय रूप से अभियान चला रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य जालंधर को नशा मुक्त शहर बनाना है।

पंजाब सरकार ने एक साल दौरान 108 कैदियों को अग्रिम रिहाई दी

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). पंजाब सरकार ने पिछले एक साल की अवधि के दौरान उम्रकैद की सजा भुगत रहे अच्छे आचरण के धारक 108 कैदियों के प्रति हमदर्दी जताते हुए उन्हें अग्रिम रिहा करने की पहल की है। यह कदम अच्छे आचरण वाले कैदियों को पुनर्वास का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पंजाब के जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने न्याय और पुनर्वास के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है और पंजाब की विभिन्न जेलों में अपनी उम्रकैद की सजा भुगत रहे अच्छे आचरण वाले 108 कैदियों को पिछले एक साल की अवधि के दौरान रिहा किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन व्यक्तियों को दूसरा मौका प्रदान करने के राज्य सरकार के प्रयासों को दर्शाता है, जिन्होंने अच्छा व्यवहार दिखाया है और जल्द रिहाई के लिए आवश्यक मानदंड पूरे किए हैं।

डी-वॉर्मिंग डे बच्चों की सेहत और संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास : सिविल सर्जन डॉ. गुरमीत लाल

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

सिविल सर्जन डॉ. गुरमीत लाल की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग जालंधर द्वारा "नेशनल डी-वॉर्मिंग डे" (पेट के कीड़ों से राष्ट्रीय मुक्ति दिवस) के अवसर पर वीरवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नं. 1, जालंधर कैंट में एक जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। स्कूल की मैडम कविता पाल द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. गुरमीत लाल और जिला टीकाकरण अधिकारी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया और सिविल सर्जन द्वारा स्कूली बच्चों को एल्बेंडाज़ोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई।

सेमिनार के दौरान डॉ. गुरमीत लाल ने विद्यार्थियों को सुबह के नाश्ते की महत्ता के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पोषक आहार लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि डी-वॉर्मिंग डे मनाने का उद्देश्य बच्चों के पेट में मौजूद कीड़ों को खत्म करना है। इसके तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाज़ोल की गोलियां खिलाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि पेट में कीड़े होने से बच्चों में एनीमिया, भूख न लगना, कुपोषण, मानसिक और बौद्धिक कमजोरी, थकावट, बेचैनी, पेट दर्द, मिचली, चिड़चिड़ापन, उल्टी और दस्त या मल में खून आने जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इससे बच्चा धीरे-धीरे कमज़ोर व थका हुआ महसूस करता है।

ब्रिटिश हाई कमीशन के राजनीतिक सलाहकार ने की मंत्री संजीव अरोड़ा के साथ मुलाकात

चंडीगढ़ (जालंधर ब्रीज). ब्रिटिश हाई कमीशन के राजनीतिक सलाहकार डैनियल शेरी ने वीरवार को उद्योग भवन, चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा के साथ 'वीज़ा फ्रॉड से बचो' मुहिम के संबंध में विशेष मुलाकात की। यह मीटिंग पंजाब के नौजवानों के हितों और भविष्य को ध्यान में रखते हुये की गई, जिसमें विदेश यात्रा के नाम पर धोखाधड़ी, ग़ैर-कानूनी एजेंटों और जाली दस्तावेज़ों के रूप में उभर रही चुनौतियों पर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान उन्होंने लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही जागरूकता मुहिमों को और तेज करने के साथ-साथ ऐसी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए सांझे तौर पर काम करने की इच्छा जतायी।

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सिराज ने लगाई लंबी छलांग, यशस्वी पहुंचे 5वें नंबर पर

स्पोर्ट्स डेस्क. आईसीसी ने ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में ओवल टेस्ट के हीरो रहे मोहम्मद सिराज को बड़ा फायदा हुआ है। सिराज ने 12 स्थान की लंबी छलांग लगाई है। साथ ही यशस्वी जायसवाल टॉप 5 में आ गए हैं। सिराज इससे पहले टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग लिस्ट में 27वें स्थान पर थे। जबकि जायसवाल अब टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में रविंद्र जडेजा को 3 स्थान का नुकसान हुआ है, वह 14 से 17वें स्थान पर खिसक गए हैं। सिराज ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में कुल 9 विकेट लिए थे। उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल किया था। इस बेहतरीन प्रदर्शन के कारण भारत ने मैच 6 रनों से जीत लिया था। सिराज को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर चुना गया। सिराज आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 674 रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। उन्होंने लंबी छलांग लगाई है।

फोटो-बीसीसीआई

यशस्वी जायसवाल टॉप 5 बल्लेबाजों में शामिल: पांचवें टेस्ट में शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 3 पायदान ऊपर छलांग लगाई है। वह टॉप 5 में शामिल हो गए हैं, वह पहले 8वें नंबर पर थे और अब 792 रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर आ गए हैं। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक एक स्थान ऊपर जाकर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज का ताज जो रूट के पास ही है।

भाजपा वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा ने उच्च न्यायालय बार पदाधिकारियों से की मुलाकात

जालंधर (जालंधर ब्रीज). भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट सुभाष शर्मा ने वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का दौरा किया और वहां बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने बार प्रधान सरतेज नरूला, वाइस प्रेसिडेंट निलेश सहित अन्य पदाधिकारियों के साथ अधिवक्ताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा लीगल सेल पंजाब के संयोजक अधिवक्ता एनके वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल भी विशेष रूप से मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस पार्किंग की लगातार बढ़ती समस्या, कोर्ट परिसर में बुनियादी सुविधाओं की कमी, तथा अधिवक्ताओं के सामने आने वाली अन्य चुनौतियों पर रहा। बैठक के दौरान एनके वर्मा ने विशेष रूप से बार प्रधान सरतेज नरूला के समक्ष पार्किंग की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय परिसर में पार्किंग व्यवस्था दिनों-दिन बदहाल होती जा रही है, जिससे अधिवक्ताओं को प्रतिदिन लंबी कतारों में लगने की परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इसका प्रतिकूल प्रभाव उनके समय पर कोर्ट पहुंचने और समुचित न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ रहा है। उन्होंने इस समस्या के तत्काल और स्थायी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

बार प्रधान नरूला ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाएगा और अधिवक्ताओं को राहत पहुंचाने हेतु व्यावहारिक समाधान जल्द निकाला जाएगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at DB Corp Ltd, Near Subhanpur Bus Stand,Hamira, Kapurthala-144802(Punjab) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.